KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual

PRABHU SIR

राष्ट्रपति

↓

राज्यपाल Governor

राज्यपाल Governor

राज्य का प्रमुख
संघ का प्रतिनिधि

यह राज्य का प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख है। He is the first citizen and constitutional head of the state.

अनु 153 - प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। Every state will have a governor.

आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल एक से अधिक राज्यों की देख रेख कर सकेगा - 7CAA 1956 के द्वारा
If required, the governor can look after more than one state - through 7CAA 1956.

ऐसी स्थिति में वेतन भत्ता का निर्धारण राष्ट्रपति कर सकेगा। In such a situation, the President can determine the salary allowance.

अनु 154 - राज्य के कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। The power of the state executive will be vested in the governor.

अनु 157- योग्यता -Qualification –

1. भारत का नागरिक हो। Should be a citizen of India.
2. न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चूका हो। Should have completed the minimum age of 35 years.
3. लाभ के पद नहीं हो। Should not hold any office of profit.
4. विधान सभा में सदस्य बनाने की योग्यता रखता हो। Should have the qualification to become a member of the Legislative Assembly.

अनु 155 - नियुक्ति - राष्ट्रपति के द्वारा।
Appointment - By the President.

अनु 156: राज्यपाल का कार्यकाल-Tenure of Governor -

1. राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त। (सामान्यतः 5 वर्ष तक) Till the pleasure of the President. (Generally up to 5 years)
2. इससे पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है।Before this, he can leave his post by submitting resignation to the President.
3. इनको पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान में निहित नहीं है। The process of removing them from the post is not contained in the Constitution.

राज्यपाल की शर्त

अनु 158 - राज्यपाल संसद के किसी भी सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि वह संसद के किसी भी सदन का या विधानमंडल के किसी भी ऐसे सदन का सदस्य है यदि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उसी दिन से सदन का पद रिक्त समझा जायेगा।The Governor shall not be a member of either House of Parliament or any House of the Legislature of the State, and if he is a member of either House of Parliament or any such House of the Legislature, if he is appointed as the Governor of a State, then the post of the House shall be deemed to be vacant from the same day.

अनु 159 - राजयपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जायेगा। The Governor shall be sworn in by the Chief Justice of the High Court of that State. According to .

अनु 160 -राष्ट्रपति किसी भी आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकता है, जो वह उचित समझता है। the President may make such provision for the discharge of the functions of the Governor in any emergency situation,

कार्य या शक्ति – Functions or Powers -

1. विधायी शक्ति Legislative Power
2. प्रशासनिक शक्ति Administrative Power
3. न्यायिक शक्ति Judicial Power

1. विधायी शक्ति Legislative Power –

KGS: UP Exam → Video

1. राज्य के विधान मंडल का एक अंग होगा। जिसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। It shall be a part of the Legislature of the State. Without whose signature no Bill can become a law.
2. यह विधान मंडल के दोनों सदनों के सत्र को आहूत और सत्रावसान कर सकेगा। It may convene and adjourn the session of both the Houses of the Legislature.
3. विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक समझ नहीं आये तो ,राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए आरक्षित कर सकेगा। यदि उसी विधेयक को पुनः राष्ट्रपति को भेजा जाय तो राष्ट्रपति उसपर हस्ताक्षर करने के लिए वाद्य नहीं होगा। -अनु 200 → कनाडा

If a Bill passed by the Legislature is not understood, it may be reserved for the President for signature. If the same Bill is sent to the President again, then the President shall not be obliged to sign it. -Article 200

4. अनु 213 - राज्यपाल का अध्यादेश - Governor's Ordinance -

जब विधान सभा सत्र में नहीं होतो राज्यपाल विधान सभा के विधि बनाने के शक्ति के बराबर अध्यादेश जारी कर सकेगा। When the Legislative Assembly is not in session, the Governor can issue an ordinance equal to the power of the Legislative Assembly to make laws.

→ विधानसभा में सत्र में नहीं हो तो।

अध्यादेश की अधिकतम अवधी 6 माह + 6 सप्ताह होगा। The maximum duration of the ordinance will be 6 months + 6 weeks.

→ विधानसभा के सत्र के आने बाद

2. प्रशासनिक शक्ति- Administrative power -

1. राज्य के कार्यपालिका की शक्ति इनमे निहित होगी । The power of the state executive will be vested in them. (राज्यपाल)
2. अनु 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकेगा। Under Article 356, they can recommend President's rule.
3. यह राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर जैसे महाधिवक्ता , राज्य निर्वाचन आयोग , राज्य वित्त आयोग , राज्य लोक सेवा आयोग , न्यायाधीश , राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री परिषद् की नियुक्ति करता है। It appoints important posts in the state such as Advocate General, State Election Commission, State Finance Commission, State Public Service Commission, Judge, Vice Chancellor of State University, Chief Minister and Council of Ministers of the state.

3.न्यायिक शक्ति - Judicial power

अनु 161 – राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति - Governor's power of pardon –

उच्चतम न्यायालय , सेना दवारा या मृत्यु दंड को छोड़ कर अन्य सभी प्रकार के दंड को क्षमा ,परिहार , लघुकरण , विराम. या निलंबित कर सकेगा। The Supreme Court can pardon, remit, commute, stop or suspend all types of punishment except military or death penalty.

भारत की प्रथम महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल - सरोजनी नायडू

First woman Governor of India and first Governor of Uttar Pradesh - Sarojini Naidu

"राज्यपाल सोने के पिजरे में बंद तोता है "- सरोजनी नायडू

'The Governor is a parrot locked in a golden cage"

- Sarojini Naidu

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING